(b) if so, by when Government would disclose the outcome of the Bofors probe and the reasons for the delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (*SHRI* S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) Yes, Sir. In response to the brief discussion of this matter in the Sabha on 25th February, 1997, the government had briefly outlined the reasons for its inability to make public the information contained in the documents furnished by the Swiss authorities.

(b) The CBI has reported that as investigations are required to be conducted in various foreign countries also, it is not possible to specify a time frame for conclusion of the same.

वर्गों के लिए विशेष भर्ती अभियान

1339. **श्री अजीत जोगी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है तथा इन वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा-निगमों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए जुलाई, 1996 में शुरू किया गया विशेष भर्ती अभियान इस समय चल रहा है।

कार्मिक विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.7.96 को सीधी भर्ती से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 19,381 बकाया रिक्तियों की इस अभियान के अन्तर्गत भरे जाने हेतु पहचान की गयी है।

सभी विभागों को बकाया रिक्तियों को 31.3.1997 तक भरने के लिए कहा गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Money Spent on the Investigation of Bofors Gun Deal

1340. SHRI M.A. BABY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the exact amount of money alleged to have been paid illegally for the Bofors gun contract; and

(b) the amount of money spent by the investigating agencies and Government, as part of investigation into the scam, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) As the Bofors case investigation is still going on, it is not possible to specify at this stage any amount as having been paid illegally for the Bofors Gun contract.

(b) *Before FIR*

Indian Currency:	Rs. 4,21,894/-
US $	9,205.53
S. Fr	610.00
Stg £	197.50
Lebanese	150.00

After FIR

Indian Currency:	Rs. 8,42,730/-
Stg £	854/-
US $	77300.50
UAE Dir.	1407.48
S. Fr	73,170.00
SEK	438485.00